



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(प्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 5 दिसम्बर, 2005/14 अग्रहायण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 9 नवम्बर, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एच० (4) 83/77-8585-8590.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शौली द्वारा निष्पादित विकास कार्य में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग बारे शिकायत पत्र की छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर एवं उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण) पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाई गई और शिकायत-पत्र में वर्णित विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (विकास) रामपुर, हिमाचल प्रदेश से करवाया गया। उपरोक्त रिपोर्टों व पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के अन्तर्गत पाया गया कि ग्राम पंचायत शौली ने मुरम्मत पैदल मार्ग खाटल गाड़ से धरारा के निष्पादन का कार्य श्रीमती विजया देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शौली को सौंपा था। जांच अनुसार इस कार्य पर कुल व्यय म० 14,494.00 रुपये दर्शाया गया है तथा सहायक अभियन्ता (विकास), रामपुर द्वारा इस कार्य की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार कार्य का मूल्य रु० 11,410.00 रुपये आंका गया है, जो व्यय राशि से म० 3,084.00 रुपये कम है।

इस प्रकार श्रीमती विजया देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शौली ने म० 3,084.00 रुपये का छह हरण/दुरुपयोग किया है, जो श्रीमती विजया देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शौली से वाजिबी वसूली है।

उक्त अनियमितता/दुरुपयोग के सन्दर्भ में श्रीमती विजया देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली के इस कार्यालय के पृष्ठांकन सम संख्या 6675-80, दिनांक 20-9-2005 के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस में 15 दिनों के भीतर-भीतर लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि श्रीमती विजया देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट नहीं हुए क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है, जिसके फलस्वरूप श्रीमती विजया देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली को मु० 3,084.00 रुपये के छलहरण/दुरुपयोग के मामले में दोषी पाये जाने के कारण उन्हें सदस्य पद से निलम्बित किया जाना उचित है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला उन शक्तियों को जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1) के अधीन प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्रीमती विजया देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड रामपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूँ तथा उन्हें यह भी आदेश देता हूँ कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल या अचल सम्पत्ति व अन्य अभिलेख हों तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत शोली को तुरन्त सौंप दें।

शिमला, 9 नवम्बर, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एस एम० एल० (4) 83/77-8579-8584.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शोली द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग वाले शिकायत-पत्र की छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर एवं उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण) पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाई गई और शिकायत-पत्र में वर्णित विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (विकास) रामपुर, हिमाचल प्रदेश से करवाया गया। उपरोक्त रिपोर्टों व पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के अन्तर्गत पाया गया कि ग्राम पंचायत शोली ने निर्माण रास्ता नोटी से कराळा के निष्पादन का कार्य श्रीमती रंजना देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली को सौंपा था। जांच रिपोर्ट अनुसार इस कार्य पर कुल व्यय मु० 10,534.00 रुपये दर्शाया गया है तथा सहायक अभियन्ता (विकास), रामपुर द्वारा इस कार्य की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार कार्य का मूल्य मु० 1,552.00 रुपये आंका गया है, जो व्यय राशि में से मु० 8,992.00 रुपये कम है।

इस प्रकार श्रीमती रंजना देवी सदस्या, ग्राम पंचायत शोली ने मु० 8,982.00 रुपये का छलहरण/दुरुपयोग किया है, जो श्रीमती रंजना देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली से काबिले वसूली है।

उक्त अनियमितता/दुरुपयोग के सन्दर्भ में श्रीमती रंजना देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली को इस कार्यालय के पृष्ठांकन सम संख्या 6681-86, दिनांक 20-9-2005 के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस में 15 दिनों के भीतर-भीतर लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि श्रीमती रंजना देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली द्वारा निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उन पर लगाया आरोप प्रमाणित होता है तथा मु० 8,982.00 रुपये के छलहरण/दुरुपयोग के मामले में दोषी पाये जाने के कारण उन्हें सदस्य पद से निलम्बित किया जाना उचित है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला उन शक्तियों को जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के 142(1) के अधीन प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्रीमती रंजना देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड रामपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूँ तथा उन्हें यह भी आदेश देता हूँ कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल या अचल सम्पत्ति व अन्य अभिलेख हों तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत शोली को तुरन्त सौंप दें।

शिमला, 9 नवम्बर, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एम० एम० एस० (4) 83/77-8573-8578.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शोली द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग वारे शिकायत पत्र की छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर एवं उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण) पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाई गई और शिकायत पत्र में वर्णित विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (विकास), रामपुर, हिमाचल प्रदेश से करवाया गया। उपरोक्त रिपोर्टों व पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टों के अन्तर्गत पाया गया कि ग्राम पंचायत शोली ने मुरम्मत पैदल मार्ग ज़ामटा से करांटा के निष्पादन का कार्य श्रीमती मेधा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली को सौंपा था। जांच अनुसार इस कार्य पर कुल व्यय रु० 16,900.00 रुपये दर्जिया गया है तथा सहायक अभियन्ता (विकास) रामपुर द्वारा इस कार्य की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार कार्य का मूल्य रु० 13,620.00 रुपये आंका गया है, जो व्यय राशि से रु० 3,280.00 रुपये कम है।

इस प्रकार श्रीमती मेधा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली ने रु० 3,280.00 रुपये का छलहरण/दुरुपयोग किया है, जो श्रीमती मेधा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली से काबिले वसूली है।

उक्त अनियमितता/दुरुपयोग के सन्दर्भ में श्रीमती मेधा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली को इस कार्यालय के पृष्ठांकन सम संख्या 6669-74, दिनांक 20-9-2005 के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस में 15 दिनों के भीतर-भीतर लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि श्रीमती मेधा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से अधो-हस्ताक्षरी सन्तुष्ट नहीं हुये, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है, जिसके फलस्वरूप श्रीमती मेधा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली को रु० 3,280.00 रुपये के छलहरण/दुरुपयोग के मामले में दोषी पाये जाने के कारण उन्हें सदस्य पद से निलम्बित किया जाना उचित है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला उन शक्तियों को जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1) के अधीन प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये श्रीमती मेधा देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड रामपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूँ तथा उन्हें यह भी आदेश देता हूँ कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल या अचल सम्पत्ति व अन्य अभिलेख हों तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत शोली को तुरन्त सौंप दें।

शिमला, 9 नवम्बर, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एम० एम० एस० (4) 83/77-8567-8572.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शोली द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग वारे शिकायत पत्र की छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर एवं उप-नियन्त्रक (अंकेक्षण) पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाई गई और शिकायत पत्र में वर्णित विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (विकास) रामपुर, हिमाचल प्रदेश से करवाया गया। उपरोक्त रिपोर्टों व पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टों के अन्तर्गत पाया गया कि निम्न विकास कार्यों का मूल्यांकन गलत राशि से कम आंका गया है, जिसके लिये श्रीमती जीवन्ती देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शोली दोषी है :—

(रशि राशियों में)

क्र० सं०	विकास कार्य का नाम	शीर्ष	व्यय राशि	मूल्यांकित राशि	अधिक व्यय
1.	निर्माण रास्ता मोटी करांटा	जे० आर० वाई०	10,534	1,552	8,982
2.	निर्माण सोलिंग ग्राम लौहाटी	एस० जी० आर० वाई०	19,580	11,792	7,788
3.	निर्माण रास्ता डांडा खनोग	जे० आर० वाई०	22,785	15,288	7,497

यह कि उपरोक्त क्र० सं० 1 व 3 पर वर्णित विकास कार्यों पर सम्बन्धित पंचायत पदाधिकारियों द्वारा व्यय मूल्यांकित राशि में अतिरिक्त व्यय करके सरकारी धन का छन हरण/दुरुपयोग किया है, जबकि प्रत्येक कार्यों को पूर्ण करने व राशि के सही उपयोग करने का दायित्व प्रधान का होता है।

यह कि उपरोक्त क्र० सं० 2 पर वर्णित विकास कार्य सोनिंग ग्राम लोहाटी के लिये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला परिषद ने रु० 20,000.00 रुपये स्वीकृत किये थे, परन्तु पंचायत ने इस योजना के बजाये लोहाटी से खदेच व चौकी की मरम्मत का कार्य किया है, जबकि जांच रिपोर्ट में जो मसूदा जारी किये गये हैं वह सोनिंग ग्राम लोहाटी के नाम से है। इस कार्य के निष्पादन पर रु० 19,580.00 रुपये उल्लेखित किये गये हैं। जबकि पुनर्मूल्यांकन करने पर इस कार्य का मूल्य 11,792.00 रुपये आंका गया है। इस प्रकार प्रधान, ग्राम पंचायत से मनमाने ढंग से कराये गये विकास कार्य के कारण विकास खण्ड अधिकारी, रामपुर द्वारा 19,580.00 की वसूली हेतु सिफारिश की गई है।

यह कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर वर्णित विकास कार्यों के निष्पादन में रु० 36,059.00 रुपये का छन हरण/दुरुपयोग प्रधान तथा पंचायत पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है।

यह कि उपरोक्त कृत्यों के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा कारण बताओ नोटिस नमबंरक 158/कांन संख्या 6652-56, दिनांक 20-9-2005 को श्रीमती जिवनी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला को जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निवृत्त किया जाये तथा 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से आरोपों पर आता सन्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था, परन्तु बिना किसी समाप्त होने पर भी न तो उक्त प्रधान का कोई उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है और न ही उसने व्यक्तिगत रूप से ही अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों बारे कुछ भी नहीं कहना है और लगाये गये आरोप सत्य हैं।

यह कि आरोपित आरोपों व विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं व धन के दुरुपयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती जिवनी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शोली अपने कार्य व कर्तव्य को हिमाचल प्रदेश पंचायतों राज अधिनियम, 1994 व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन निभाने में असफल रही है।

अतः मैं, एन० के० बी० एम० नेगी, उपायुक्त, शिमला उन शक्तियों के प्रतीक जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 में निहित है का प्रयोग करते हुए श्रीमती जिवनी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शोली को प्रधान पद से तुरन्त निवृत्त करना है और आदेश देता हूँ कि यदि उसके पास कोई ग्राम पंचायत की सरकारी धन राशि प्रयास पंचायत का स्टॉक मागाना खाता हो तो उसे तत्काल सम्बन्धित पंचायत सचिव/महानगर ग्राम पंचायत शोली को सौंप दें।

शिमला, 9 नवम्बर, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एम० एम० एल० (4) 83/77-8561-8566.—यह कि जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शोली द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग बारे शिकायत पत्र की छातरी व खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर एवं उप-निष्पक्ष (अंकेक्षण) पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाई गई और शिकायत पत्र में वर्णित विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (विकास) रामपुर, हिमाचल प्रदेश से कराया गया। उपरोक्त रिपोर्टों व पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के अन्तर्गत पाया गया कि ग्राम पंचायत शोली ने निर्माण रास्ता ठाडा से खनो के निष्पादन का कार्य श्री चतन लाल शर्मा, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली को सौंपा था। जांच रिपोर्ट अनुसार इस कार्य पर कुल व्यय रु० 22,785.00 रुपये दर्शाया गया।

है तथा सहायक अभियन्ता (विकास), रामपुर द्वारा इस कार्य को पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार कार्य का मूल्य रु० 15,288.00 रुपये आंका गया है, जो व्यय राशि रु० 7,497.00 रुपये कम है।

इस प्रकार श्री चमन लाल शर्मा, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली ने रु० 7,497.00 रुपये का छलहरण/दुरुपयोग किया है, जो श्री चमन लाल शर्मा, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली से काबिले बमूली है।

उक्त अनियमितता/दुरुपयोग के सन्दर्भ में श्री चमन लाल शर्मा, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली को इस कार्यालय के पुष्ठांकन सम संख्या 6663-68, दिनांक 20-9-2005 के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस में 15 दिनों के भीतर-भीतर लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि श्री चमन लाल शर्मा, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली द्वारा निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उन पर लगाया आरोप प्रमाणित होता है तथा रु० 7,497.00 रुपये के छलहरण/दुरुपयोग के मामले में दावी पाये जाने के कारण उन्हें सदस्य पद से निलम्बित किया जाना उचित है।

अतः मैं, एस० के० बी० एम० नेगी, उपायुक्त, जिला उन शक्तियों के जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142(1) के अधीन प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये श्री चमन लाल शर्मा, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड रामपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूँ तथा उन्हें यह भी आदेश देता हूँ कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत को कोई चन्दा या संपत्ति व अन्य अभिलेख हों तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत शोली को तुरन्त सौंप दें।

शिमला, 9 नवम्बर, 2005

संख्या पी० सी० एच० एम० एम० एल० (4) 83/77-8555-8560.—यह कि जिला जिल्ला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम पंचायत शोली द्वारा निष्पादित विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग बारे शिकायत पत्र की छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर एवं उप-निष्पन्न (अंकेजग) पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाई गई और शिकायत पत्र में वर्णित विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (विकास, रामपुर, हिमाचल प्रदेश से करवाया गया। उपरोक्त रिपोर्टों व पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत ने स्वीकृत योजना सोलिंग ग्राम लोहाटी के निष्पादन का कार्य श्री रूप सिंह नेगी, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली का सौंपा था, किन्तु पंचायत सदस्य द्वारा स्वीकृत कार्य के स्थान पर मतमाने ढंग से खदेव व चौकी नामक स्थान में लोहाटी गांव तक पैदल चलने योग्य रास्तों की मुरम्मत का कार्य किया है। इस कार्य पर कुल व्यय रु० 19,580.00 रुपये दर्शाया गया है। सर्जि से किये गये कार्य का मूल्यांकन करवाने पर उन कार्यों का मूल्य रु० 11,041.00 रुपये आंका गया है तथा पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार कार्य का मूल्य रु० 11,792.00 रुपये आंका गया है, जो व्यय राशि से क्रमशः रु० 8,539.00 रुपये तथा 7,788.00 रुपये कम हैं। किन्तु खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर की रिपोर्ट अनुसार सम्बन्धित से रु० 19,580.00 रुपये की बमूली हेतु निम्ना है।

इस प्रकार श्री रूप सिंह नेगी, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली ने स्वीकृत योजना के स्थान पर अज्ञात गली व उपरोक्त रास्तों की मुरम्मत का कार्य किया है, जिस कारण स्वीकृत योजना का कार्य नहीं हो पाया है, इसलिए श्री रूप सिंह नेगी ने रु० 19,580.00 रुपये का छलहरण/दुरुपयोग किया है, जो उनसे काबिले बमूली है।

यह कि उपरोक्त अनियमितता/दुरुपयोग के सन्दर्भ में श्री रूप सिंह नेगी, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली का इस कार्यालय के पुष्ठांकन सम संख्या 6657-62, दिनांक 20-9-2005 के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस में 15 दिनों के भीतर-भीतर लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि श्री रूप सिंह नेगी, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली द्वारा निर्धारित प्रवधि में कोई साठरीकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उन पर लगाया आरोप प्रमाणित होता है तथा रु० 19,580.00 रुपये के छलहरण/दुरुपयोग के मामले में दोषी पाये जाने के कारण उन्हें सदस्य पद से निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला उन शक्तियों को जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1) के अधीन प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये श्री रूप सिंह नेगी, सदस्य, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड रामपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूँ तथा उन्हें यह भी आदेश देता हूँ कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत को कोई चन या अचल सम्पत्ति व अन्य अभिलेख हों तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत शोली को तुरन्त सौंप दें।

एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, हिमाचल प्रदेश।